भारतीय संसद पर आतंकवादी हमले के एक अभियुक्त अफजल गुरु को फांसी दिये जाने पर

–अरुण जेटली

13 दिसम्बर, 2001 को भारतीय संसद पर आतंकवादियों ने हमला किया। संसद की रक्षा के लिए वहां तैनात कई सुरक्षा और पुलिसकर्मियों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिये। संसद के भीतर जो भी लोग थे उन्होंने एक स्वर में हमले पर दुख व्यक्त किया। हम सभी ने प्रतिबद्धता व्यक्त की कि किसी को यह सोचने की इजाजत नहीं दी जाएगी कि भारत "सॉफ्ट स्टेट" है और इस बात को दोहराया कि हमले के लिए दोषियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। हमारे बहादुर सुरक्षाकर्मियों ने हमले के स्थान पर ही हमलावरों को धर दबोचा। अन्य साजिशकर्ताओं से पूछताछ की गई, उन पर मुकदमा चलाया गया और उनमें से कुछ को दोषी ठहराया गया। लेकिन सुरक्षाकर्मियों द्वारा समय पर कार्रवाई करने के कारण कोई भी आतंकवादी संसद की इमारत के अंदर प्रवेश नहीं कर पाया। हमलावरों की भारत के राजनेताओं के बड़े वर्ग को निशाना बनाने की योजना विफल हो गई।

हमने कई आतंकवादी हमले देखें। इनमें से अधिकतर की योजना सीमापार बनाई गई थी जिसे भारत में अंजाम दिया गया। कुछ ठिकाने बड़ी सावधानी से चुने गए। इनमें भारतीय संसद, जम्मू कश्मीर विधानसभा, अक्षरधाम मंदिर और मुंबई शहर शामिल हैं। ये सभी स्थान भारत के संसदीय लोकतंत्र, संप्रभुता, सांस्कृतिक विरासत और अर्थव्यवस्था के प्रतीक हैं। भारतीय संसद पर हमला भारत पर हमला है। भारत ने हमले की एक स्वर में निंदा की।

भारत में व्यवस्था कानून के शासन से चलती है। हमारी पुलिस एजेंसियों द्वारा की गई जांच को अदालतें कड़ाई और बारीकी से देखती हैं। लंबे समय तक चले मुकद्दमें, उच्च न्यायालय में अपील और आखिर में उच्चतम न्यायालय में अपील के बाद हमारी न्यायिक व्यवस्था ने सबूतों की सावधानीपूर्वक एवं बारीकी से जांच की। अफजल गुरु के मामले में सभी न्यायिक प्राधिकारियों ने उसके अपराध की पुष्टि की और मृत्युदंड को बरकरार रखा। उसकी दया याचिका को राष्ट्रपति ने अस्वीकार कर दिया। सरकार यह बताने में असमर्थ थी कि उसे सजा देने के मामले में देरी क्यों की जा रही है। लेकिन आखिरकार कानून ने अपना समय लिया। जनभावना ने सरकार को कार्रवाई करने और कानून लागू करने के लिए बाध्य कर दिया। 13 दिसम्बर, 2001 की तरह भारत को आज भी एक स्वर में अपनी बात रखनी चाहिए और दुनिया को स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि भारत "सॉफ्ट स्टेट" नहीं है। भारत की संप्रभुता और उसके संस्थानों पर जो भी हमला करेगा, उसकी जवाबदेही तय की जाएगी। चाहे देर से ही सही, न्याय तो हुआ।